RNI No.: UPHIN/25/A1698
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

नवसर्जन संस्कृति

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 277
दि. 08.02.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत-मलेशिया संबंध हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

आज दुनिया भारत को विकास के एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में में देखती है, चाहे यूके, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान, यूरोपीय संघ हो या अमेरिका—सभी देश भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं, आज भरोसा ही भारत की सबसे बड़ी मुद्रा (करेंसी) बन गया है : प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यहाँ जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया है, वह हमारी साझा संस्कृति की सुंदर विविधता को दशार्ता है। उन्होंने इस उत्सव में शामिल होने के लिए अपने प्रिय मित्र, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम स्वयं उनका स्वागत करने एयरपोर्ट आए और अपनी कार में बैठाकर उन्हें कार्यक्रम स्थल तक लाए। श्री मोदी ने कहा, "प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का यह विशेष भाव भारत के प्रति उनके प्रेम और सम्मान को दशार्ता है, साथ ही यहाँ मौजूद आप सभी लोगों के प्रति उनके आदर को भी प्रकट करता है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि 800 से अधिक नर्तकों द्वारा पूरी लय और ताल के साथ दी गई रिकॉर्ड सांस्कृतिक प्रस्तुति आने वाले कई वर्षों तक याद रखी जाएगी। उन्होंने इस शानदार प्रदर्शन के लिए सभी कलाकारों को बधाई दी। श्री मोदी ने बताया कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वे तब से मित्र हैं, जब वे प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे। उन्होंने सुधारों के प्रति प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के दृष्टिकोण, उनकी शानदार बौद्धिक क्षमता और 2025 में आसियान के अध्यक्ष के रूप में उनके कुशल नेतृत्व की सराहना की।

प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि वह पिछले साल आसियान शिखर सम्मेलन के लिए मलेशिया नहीं आ पाए थे, लेकिन तब उन्होंने जल्द ही यहाँ आने का वादा किया था और आज उन्होंने अपना वह वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने बताया कि साल 2026 की यह उनकी पहली विदेश यात्रा है और उन्हें खुशी है कि वे त्योहारों के इस मौसम में भारतीय समुदाय के बीच हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी ने संक्रांति, पोंगल और थाइपुसम का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया होगा। उन्होंने आगे आने वाले त्योहारों—शिवरात्रि, रमजान की शुरूआत और हरि राया के

लिए भी सभी को ढेरों शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मलेशिया में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय मूल का समुदाय निवास करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत और मलेशिया के लोगों के दिलों को जोड़ने वाली बहुत सी बातें हैं। कार्यक्रम से पहले देखी गई एक प्रदर्शनी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें दोनों देशों के रिश्तों को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। श्री मोदी ने कहा, "भारतीय मूल का समुदाय दोनों देशों को जोड़ने वाला एक जीता-जागता सेतु है।" उन्होंने खान-पान और संस्कृति का उदाहरण देते हुए बताया कि मलेशिया की रोटी कनाई और भारत का मालाबार परोटा एक जैसे हैं। नारियल, मसाले और यहाँ की तेह तारिक का स्वाद कुआलालंपुर और कोच्चि, दोनों जगह एक जैसा ही महसूस होता है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि दोनों देशों के लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि भारतीय भाषाओं और मलय भाषा में कई शब्द एक जैसे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय फिल्में और संगीत मलेशिया में बहुत लोकप्रिय हैं। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम बहुत अच्छा गाते हैं और यह जानकर बहुत खुशी होती है कि उन्हें महान कलाकार एमजीआर के तमिल गीत भी बहुत पसंद हैं।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मलेशिया के भारतीय मूल के समुदाय के दिलों में भारत के लिए एक खास जगह है। साल 2001 की एक घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब उनके गृह राज्य गुजरात में भूकंप आया था, तब यहाँ के समुदाय के बहुत से लोग मदद के लिए आगे आए थे। उन्होंने इसके लिए सभी का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने भावुक होते हुए कहा, "मलेशिया में रहने वाले इस समुदाय के हजारों पूर्वजों ने भारत को आजाद कराने के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए थे। उनमें से कई ने कभी भारत को देखा तक नहीं था, फिर भी वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होने वाले शुरूआती लोगों में से थे।" प्रधानमंत्री ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में ही मलेशिया स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर उनके नाम पर रखा गया है। उन्होंने मलेशिया में नेताजी सर्विस सेंटर और नेताजी वेलफेयर फाउंडेशन की सराहना की और उनके प्रयासों को नमन किया।

प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने सदियों से अपनी परंपराओं को बनाए रखा है। उन्होंने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने पूरे भारत को बताया था कि मलेशिया के 500 से ज्यादा स्कूलों में बच्चों को भारतीय भाषाएं सिखाई जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा, "मलेशिया में संत तिरुवल्लुवर और स्वामी विवेकानंद का प्रभाव साफ दिखाई देता है। अभी हाल ही में बाटू केव्स में हुए थाईपुसम उत्सव की भव्यता अद्भुत थी, जो भारत के पलानी के उत्सवों की याद दिलाती है।" प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि मलेशिया में गरबा काफी लोकप्रिय है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने सिख समुदाय के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को बहुत महत्व देता है, जो यहाँ श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिल दुनिया के लिए भारत का उपहार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तमिल साहित्य शाश्वत है, तमिल संस्कृति वैश्विक है और तमिल लोगों ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से मानवता की सेवा की है। श्री मोदी ने रेखांकित करते हुए कहा, "भारत के उपराष्ट्रपति थिरु सी.पी. राधाकृष्णन, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. मुरुगन, ये सभी तमिलनाडु से हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मलेशिया में रहने वाले तमिल प्रवासी विभिन्न क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रहे हैं और उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिया कि मलेशिया में तमिल समुदाय कई शताब्दियों से मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसी इतिहास से प्रेरित होकर, भारत ने यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना की थी और अब साझा विरासत को और मजबूत करने के लिए एक तिरुवल्लुवर सेंटर स्थापित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत-मलेशिया संबंध हर साल नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की नई दिल्ली यात्रा को याद करते हुए, उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।

योगी आदित्यनाथ समेत भाजपा के कई नेताओं ने रमाबाई आंबेडकर को श्रद्धांजलि दी

लखनऊ, सात फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई प्रमुख नेताओं ने शनिवार को रमाबाई आंबेडकर की जयंती पर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी।

सीएम योगी ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, "सेवा, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति, नारी चेतना की सशक्त प्रतीक माता रमाबाई आंबेडकर की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। शिक्षित व जागरूक समाज के निर्माण में उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा, "महिला सशक्तिकरण की आदर्श प्रतीक एवं सामाजिक समानता की प्रबल पक्षधर माता रमाबाई आंबेडकर की जयंती पर सादर नमन।"

राष्ट्रपति ने जगदलपुर में बस्तर पैंडम 2026 का उद्घाटन किया

(जीएनएस)।

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (7 फरवरी, 2026) जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में बस्तर पैंडम 2026 का उद्घाटन किया।

इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जब किसान इस उपजाऊ भूमि में बीज बोते हैं, जब आम का मौसम आता है, तो यह पैंडम का मौसम होता है। बस्तर के लोग जीवन के हर पहलू का उत्सव मनाते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य लोग बस्तर के लोगों से जीवन जीने का यह तरीका सीख सकते हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर की परंपराओं और संस्कृति ने हमेशा लोगों को आकर्षित किया है, लेकिन दुर्भाग्य से, यह क्षेत्र चार दशकों तक माओवाद से ग्रस्त रहा। परिणामस्वरूप, यहां के लोगों को भारी कष्ट सहना पड़ा। युवा, आदिवासी और दलित भाई-बहन सबसे अधिक प्रभावित हुए। लेकिन, भारत सरकार द्वारा माओवादी आतंक के खिलाफ उठाए गए निर्णायक कदमों के कारण, वर्षों से व्याप्त असुरक्षा, भय और अविश्वास का माहौल अब समाप्त हो रहा है। माओवाद से जुड़े लोग हिंसा का मार्ग त्याग रहे हैं, जिससे नागरिकों के जीवन में शांति लौट रही है।

राष्ट्रपति ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो पहले माओवादी गतिविधियों में शामिल थे और अब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हथियार डालकर लोग सामान्य जीवन जी सकें और मुख्य धारा में लौट सकें। उनके लिए कई विकास और कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। राज्य सरकार की 'नियाद नेल्लानार योजना' ग्रामीणों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने यह देखकर खुशी जताई कि बस्तर में विकास के एक नये समय की शुरूआत हो रही है। हर गांव में बिजली, सड़कें और पानी की सुविधा उपलब्ध हो रही है। वर्षों से बंद पड़े स्कूल फिर से खुल रहे हैं और बच्चे कक्षाओं में भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद उत्साहजनक तस्वीर है जो सभी नागरिकों के लिए खुशी का स्रोत है।

राष्ट्रपति ने हिंसा का मार्ग त्यागकर मुख्यधारा में लौटने वाले सभी लोगों की प्रशंसा की और उनसे संविधान और देश के लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए और कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों का कल्याण सरकार की विशेष प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री-जनमान योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के लाभ सबसे वंचित आदिवासी गांवों तक पहुंच रहे हैं।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि शिक्षा व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास की आधारशिला है।

आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं ताकि इन क्षेत्रों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उन्होंने सभी अभिभावकों और संरक्षकों से अपने बच्चों को शिक्षित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इसी तरह छत्तीसगढ़ और भारत का भविष्य उज्ज्वल होगा।

'हम भी आपके दादा लगते हैं' सीएम योगी ने अपने गांव पंचूर में किया रात्रि विश्राम, लोगों से मिले

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वह शुक्रवार को अपने पैतृक गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने गांव में ही रात्रि विश्राम किया। शनिवार सुबह वह अपने गांव की सैर पर निकले और बड़े-बुजुर्गों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से मुलाकात की और उनका बाल प्रेम उमड़ आया।

बच्चे से बोले- हम भी तुम्हारे दादा जैसे

गांव में भ्रमण के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बड़े-बुजुर्गों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट और टाफियां दीं। एक बच्चे को उन्होंने चॉकलेट दी तो वह अपने दादा को देने लगा तो सीएम ने कहा कि हम भी तुम्हारे दादा जैसे हैं। यह चॉकलेट आप खा लो यह खाने की चीज है।

उन्होंने गांव के बच्चों पर अपना स्नेह बरसाया, उनसे देर तक बातचीत की और उन्हें चॉकलेट भी दी। सीएम योगी ने एक बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसे प्रेम से खिलाया। बच्चों ने भी सहज भाव से मुख्यमंत्री से बातचीत की। इस दौरान, गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी भी ली।

शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे थे सीएम योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे थे। उन्होंने और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक स्थित बिथ्याणी में जनता इंटर कॉलेज के नव निर्मित भवन का लोकार्पण किया था। इस मौके पर सीएम योगी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उल्लेख करते हुए कहा था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था आज एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। यह नीति विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने की बजाय उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सक्षम बनाने पर केंद्रित है।

भारतीय तटरक्षक बल ने समन्वित समुद्री-हवाई अभियान के जरिए अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया

भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) ने 5-6 फरवरी 2026 को एक सुनियोजित समुद्री-हवाई समन्वित अभियान के जरिए एक अंतरराष्ट्रीय तेल तस्करी रैकेट का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। इस अभियान से भारी मात्रा में तेल और तेल-आधारित कार्गो के अवैध हस्तांतरण में शामिल एक जटिल नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। 5 फरवरी 2026 को, मुंबई से लगभग 100 समुद्री मील पश्चिम में भारतीय तटरक्षक बल के जहाजों ने तीन संदिग्ध जहाजों को रोका। विशेषज्ञ बोर्डिंग टीमें जहाजों की लगातार तलाशी, जहाज पर बरामद इलेक्ट्रॉनिक डेटा की पुष्टि, दस्तावेजों का सत्यापन और चालक दल के सदस्यों से विस्तृत पूछताछ के द्वारा घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने और आपराधिक कार्यप्रणाली की पुष्टि कर पाई।

अमलाहा से देशव्यापी दलहन क्रांति का आगाज

नई दिल्ली, (जीएनएस)। मध्य प्रदेश के सीहोर ज़िले के अमलाहा स्थित खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र (ऋछफ्ढ) से आज देश की दलहन नीति और किसानझ्रकेंद्रित कृषि विमर्श का नया अध्याय जुड़ा और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में देशव्यापी दलहन क्रांति का आगाज हुआ। यहाँ आयोजित राष्ट्रीय दलहन परामर्श एवं रणनीति बैठक में एक ही मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, कई राज्यों के कृषि मंत्री, शीर्ष वैज्ञानिक, कउअफ्झ्रकउअफऊअ के प्रतिनिधि, प्रगतिशील किसान, ऋढ्ढड, बीज और दाल मिल प्रतिनिधि जुटेझ्र और संदेश साफ था: दलहन में आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप अब खेतों के बीच से तय होगा, दिल्ली के फाइलों के कमरों से नहीं।

भारत की दलहन नीति और किसान हितों के मोर्चे पर एक साथ दो बड़ी घोषणाएँ

एक तरफ अमलाहा (सीहोर) में खाद्य दलहन अनुसंधान केंद्र (FLRP) से 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' का रोडमैप तय हुआ, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि दालें आयात करना हमारे लिए शर्म की बात है, अब भारत दालों का निर्यातक बनेगा और हालिया अंतरराष्ट्रीय समझौतों के बावजूद भारत के किसान के हितों पर जरा सी भी आंच नहीं आने दी जाएगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा कि विपक्ष का ह्लदेश बेच दिया, किसान बेच दिए, किसान बर्बाद हो जाएंगेह्व वाला नैरेटिव आज के तथ्य सामने आने के बाद टिक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि यह अपने आप में एक ऐतिहासिक और अद्भुत समझौता है जिसमें भारत की प्रगति और विकास के नए द्वार खुलेंगे, निर्यात बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और किसान की आय भी बढ़ेगी।

भारत एआई इम्पैक्ट समिट समावेशी, जिम्मेदार और लचीली एआई के लिए राष्ट्रों, नवोन्मेषकों और नागरिकों को एक मंच पर लाएगा

(जीएनएस)।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भविष्य की अवधारणा नहीं है। यह पहले से ही भारतीयों के सीखने, काम करने, सेवाओं तक पहुंचने और रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने के तरीके को नया आकार दे रहा है। यह संदेश 6 फरवरी, 2026 को आयोजित डिजिटल इंडिया – आस्क अवर एक्सपर्ट्स के नवीनतम एपिसोड में केंद्र में आया, जिसमें आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट पर इंडियाएआई मिशन के सीईओ श्री अभिषेक सिंह के साथ एक आकर्षक और विचारोत्तेजक बातचीत हुई ।

इस एपिसोड में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि शिखर सम्मेलन एक जन-केंद्रित मंच के रूप में कैसे कार्य करेगा, जो तकनीकी चचाओं से परे जाकर इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शासन, स्टार्टअप, सेवाओं और रोजगार के क्षेत्र में अपने लाभ के

लिए एआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं।

इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक एआई चचाओं को जमीनी स्तर पर लोगों, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए वास्तविक और उपयोगी परिणामों में बदलना है। श्री सिंह ने कहा, "इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के माध्यम से, भारत वैश्विक एआई चर्चा को इरादे से प्रभाव की ओर ले जा रहा है – यह सुनिश्चित करते हुए कि एआई के नवाचार, कौशल और लाभ सभी के लिए सुलभ हों, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों के लिए।"

चर्चा के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि एआई किसानों को फसल नियोजन में सुधार करने, डॉक्टरों को तेजी से और अधिक सटीक निदान करने, शिक्षकों को व्यक्तिगत शिक्षण उपकरण उपलब्ध कराने, छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को तेजी से आगे बढ़ने में सहायता करने और नौकरी चाहने वालों को नए करियर विकल्प खोजने में मदद कर सकता है।

मुख्यमंत्री योगी ने महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय का किया निरीक्षण

पौड़ी : शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने महाविद्यालय परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक रेनू बिष्ट, अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, महाविद्यालय प्रशासन एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

पूर्व सांसद ने मुख्यमंत्री से मांफी मांगी-स्वतंत्रदेव के लिए तल्ख टिप्पणी, पूर्व सांसद ने इस बात पर मांगी

महोबा , (जीएनएस)।

पूर्व सांसद और विधायक के पिता गंगाचरण राजपूत का फेसबुक पर किया पोस्ट फिर वायरल हुआ। जलशक्ति मंत्री का काफिला रोकने व बयानबाजी करने पर चरखारी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष ने नोटिस जारी किया है।

प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के 30 जनवरी को जिले के दौरे के दौरान हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधायक बृजभूषण राजपूत को नोटिस जारी होने के बाद उनके पिता और पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत डेमेज कंट्रोल में लगे हैं। शनिवार को उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से माफी मांगी है। हालांकि स्वतंत्र देव को लेकर उन्होंने तल्ख टिप्पणी की। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह जलशक्ति मंत्री पर भी निशाना

साधते हुए अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पार्टी के संविधान को सर्वोपरि करार दिया है।

पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह पर सीधा निशाना साधना शुरू कर दिया है। अब तक वे खुद को मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह का अभिभावक और विधायक बृजभूषण को उनका छोटा भाई बता रहे थे लेकिन शनिवार को उन्होंने कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा कि दोनों पक्षों को बयानबाजी करने से मना किया गया था तो मंत्री ने विधायक के खिलाफ टिप्पणी क्यों की, पार्टी इन्हें भी नोटिस दे। यदि मंत्री जी को नोटिस नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि अनुशासन की तलवार सिर्फ छोटे कार्यकताओं का ही गला काटती है, बड़ों का नहीं। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी को संबोधित करते हुए लिखा कि स्वतंत्रदेव को कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के सम्मेलन में होना जरूरी था या योगी जी के साथ। किस हैसियत से मुख्यमंत्री के साथ हमेशा रहते हैं। क्या इन्होंने प्रदेशाध्यक्ष का अपमान नहीं किया क्या यह अनुशासनहीनता नहीं है। यदि है तो इस बात के लिए स्वतंत्रदेव सिंह को भी सो-कॉज नोटिस जारी होना चाहिए।

पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सनातन में संतों का सम्मान सर्वोच्च है। भगवान विष्णु ने भी भृगु के लात मारने पर भी क्षमा मांगी। मेरे पुत्र से कोई अपमान हो गया तो योगी जी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि योगी जी एक संत हैं। हम दुनिया से लड़ सकते हैं, संतों से नहीं।

जम्मू-कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज जम्मू में जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, केन्द्रीय गृह मंत्री ने सड़क बुनियादी ढांचे, जल विद्युत परियोजनाओं, बिजली, उद्योग, पर्यटन, 4ॠ और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की व्यापक समीक्षा की। बैठक में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री श्री उमर अबदुल्ला, केन्द्रीय गृह सचिव और केन्द्र सरकार और जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार, एक विकसित और समृद्ध जम्मू और कश्मीर के विजन के प्रति कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा विकास में तेजी लाने के लिए किए जा रहे निरंतर और समर्पित प्रयासों से जम्मू और कश्मीर में विकास परियोजनाओं में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को जल विद्युत परियोजनाओं के पूरी क्षमता को विकसित करने की जरूरत है । उन्होंने कहा कि

सरकार की जनकल्याण योजनाओं का 100% सैचुरेशन प्राप्त करना और सभी विकास परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलना सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाये।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि युवाओं को विकास के साथ जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने और स्पोर्ट्स अकादमियों की स्थापना पर ध्यान दिया जाए। इस विषय में विभिन्न स्पोर्ट्स बॉडीज से बात करके लगभग 200 करोड़ रुपए के निवेश की कोशिश की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि (NDDB) के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयास होने चाहिएं।

एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, जम्मू और कश्मीर को पहली बार वित्त वर्ष 2025-26 में SASCI योजना के दायरे में लाया गया है, जिससे पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 50 साल के ब्याज-मुक्त ऋण मिल सकेंगे। गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत वित्तीय अनुशासन से समय के साथ केंद्रशासित प्रदेश के वित्तीय घाटे को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश, वर्ष 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और भारत सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जम्मू और कश्मीर को पूरी सहायता देती रहेगी। गृह मंत्री श्री अमित शाह का दौरा, भारत सरकार के जम्मू और कश्मीर के विकास, शांति और सुरक्षा को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के दृढ़ संकल्प को दशार्ता है।

केंद्रीय बजट 2026-27 एक मजबूत, लचीले और तेजी से विकास कर रहे भारत के आत्मविश्वास को दशार्ता है: हरदीप सिंह पुरी

(जीएनएस)।

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज देहरादून में केंद्रीय बजट 2026-27 पर एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट 2014 के बाद से मौलिक परिवर्तन से गुजरी अर्थव्यवस्था के आत्मविश्वास और परिपक्वता को दशार्ता है। उन्होंने कहा कि बजट विकास को बढ़ावा देने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन स्थापित करता है, जो भारत की उस यात्रा को रेखांकित करता है जिसमें वह "कमजोर पांच" देशों में गिने जाने से लेकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे भरोसेमंद वैश्विक विकास गाथाओं में से एक बनने तक पहुंचा है।

बजट को दूरदर्शी और सुदृढ़ीकरण उन्मुख बताते हुए श्री पुरी ने कहा कि यह पिछले दशक में रखी गई नींव पर आधारित है और भारत को वैश्विक नेतृत्व के अगले चरण के लिए

तैयार करता है। उपभोग और निवेश से प्रेरित होकर, वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो वैश्विक वृद्धि दर लगभग 3 प्रतिशत के आसपास रहने के बावजूद, लगातार चौथे वर्ष भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।

मूल्य स्थिरता पर मंत्री जी ने 2014 से हासिल हुई तीव्र प्रगति पर प्रकाश डाला और बताया कि भारत ने 2025 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष मुद्रास्फीति में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की, जो लगभग 1.8 प्रतिशत थी। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच, खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और दालों की कम कीमतों के कारण मुद्रास्फीति औसतन लगभग 1.7 प्रतिशत रही। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में मुद्रास्फीति का स्तर कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।

श्री पुरी ने 2014 से पूंजी-आधारित विकास की ओर निर्णायक बदलाव पर जोर देते हुए कहा कि 2026-27 में कुल पूंजीगत व्यय लगभग 12.2 लाख करोड़ रुपये है, जो 2013-14 की तुलना में 430 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दशार्ता है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आवंटन में लगभग 500 प्रतिशत, रक्षा के लिए 210 प्रतिशत से अधिक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए लगभग 176 प्रतिशत और शिक्षा के लिए 110 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अवसंरचना पर किया गया खर्च विकास का एक प्रमुख इंजन बन गया है, और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास पर

भारत और सेशेल्स ने मुंबई में व्यवसाय गोलमेज वार्ता में समुद्री, ब्लू इकोनॉमी सहयोग पर चर्चा की

"महासागर विजन के तहत भारत-सेशेल्स समुद्री साझेदारी प्रगाढ़ हुई, हिंद महासागर में रणनीतिक तालमेल का संकेत": सबानंद सोनोवाल

प(जीएनएस)।

भारत और सेशेल्स ने मुंबई में आयोजित भारत-सेशेल्स व्यवसाय गोलमेज वार्ता में समुद्री व्यापार, ब्लू इकोनॉमी क्षेत्रों और सतत विकास में सहयोग को गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की। इसमें सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. पैट्रिक हर्मिनी और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सबानंद सोनोवाल ने भाग लिया।

केंद्रीय मंत्री सबानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और सेशेल्स के बीच ऐसा रिश्ता है जिसकी जड़ें इतिहास में हैं और जो लोगों के बीच स्थायी संबंधों से मजबूत हुआ है। इसमें समुद्री आदान-प्रदान आधुनिक कूटनीति से भी पहले का है। सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि यह साझेदारी साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुलवाद और आपसी सम्मान पर आधारित करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध में विकसित हुई है। इसमें विकास सहायता, क्षमता निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया सहित कई क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।

सेशेल्स के साथ भारत का जुड़ाव महासागर विजन - क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र प्रगति - द्वारा निर्देशित है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, स्थिरता और सुरक्षा पर जोर देता है।

सबानंद सोनोवाल ने कहा, "यह साझेदारी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में नई गति मिली है। पड़ोस-पहले जुड़ाव, महासागर-आधारित सहयोग और समावेशी विकास पर उनके जोर

ने सेशेल्स सहित हिंद महासागर के द्वीप राष्ट्रों के साथ भारत के जुड़ाव को स्पष्ट रणनीतिक दिशा प्रदान की है। भारत और सेशेल्स हिंद महासागर को शांति, स्थिरता और साझा समृद्धि के क्षेत्र के रूप में देखते हैं।"

सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह-आधारित विकास, लॉजिस्टिक्स, समुद्री सेवाओं और नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का अनुभव सेशेल्स की विकास प्राथमिकताओं को पूरा कर सकता है, जबकि मुंबई का वित्तीय और फिनटेक इकोसिस्टम नवाचार और वित्तीय समावेशन पहलों का समर्थन कर सकता है।

प्रगाढ़ सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करते हुए, सबानंद सोनोवाल ने कहा, "ब्लू इकोनॉमी में मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, बंदरगाह विकास, समुद्री बुनियादी ढांचा, महासागर-आधारित नवीकरणीय ऊर्जा और समुद्री अनुसंधान सहित महत्वपूर्ण गुंजाइश है। पर्यटन और आतिथ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाएं, फिनटेक, शिक्षा और कौशल विकास भी सहयोग के लिए मजबूत अवसर प्रदान करते हैं।"

भारत-सेशेल्स व्यवसाय गोलमेज वार्ता में भारत की कई व्यावसायिक संस्थाओं ने भाग लिया जो बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फिनटेक और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि मुंबई की बंदरगाह शहर के रूप में ताकत - इसके बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्री सेवाएं, शिपयार्ड और वित्तीय इकोसिस्टम - इसे समुद्री व्यापार और महासागर-आधारित उद्योगों में भारत-सेशेल्स सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए स्वाभाविक मंच बनाते हैं।

सबानंद सोनोवाल ने कहा, "मुंबई ने सदियों से दुनिया के साथ भारत के जुड़ाव का प्रतीक रहा है। समुद्र, व्यापार और उद्यम से आकार लिया हुआ, भारत और सेशेल्स दो समुद्री राष्ट्र हैं जो हिंद महासागर से जुड़े हैं और समृद्धि और सतत विकास की साझा दृष्टि से एकजुट हैं। यह दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यावसायिक सहयोग पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त स्थान है।"

भारत की व्यापक आर्थिक दिशा का जिक्र करते हुए, सोनोवाल ने कहा कि देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसे निरंतर घरेलू मांग, सुधार-उन्मुख नीतिगत माहौल और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निवेश का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में, भारत ने कराधान, कॉर्पोरेट विनियमन और डिजिटल शासन में व्यापक सुधार किए हैं, जिससे पारदर्शिता और व्यापार करने में आसानी बढ़ी है।

प्रवीणभाई की अग्नि परीक्षा ली गई और वे पूरे अंकों के साथ पास हुए: गोपाल इटालिया

एक प्रवीणभाई को जेल में डालोगे तो 500 प्रवीणभाई तैयार होंगे: गोपाल इटालिया

केशोद में आप विधायक गोपाल इटालिया और फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम की विशेष उपस्थिति में 'किसान संवाद कार्यक्रम' आयोजित किया गया

आजादी की लड़ाई के समय अंग्रेज भी भाजपा नेताओं की तरह ही सोचते होंगे: गोपाल इटालिया

भाजपा नेताओं को भी यह भ्रम है कि अगर अअढ के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो गुजरात में भाजपा ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है: गोपाल इटालिया

पहली बार भाजपा के सामने खड़े होने वाले युवा मैदान में उतरे हैं और इसी वजह से अब भाजपा वाले परेशान हो गए हैं: गोपाल इटालिया

पूरे गुजरात का भरोसा अब अअढ पार्टी पर है: गोपाल इटालिया

हम पर जो झूठे केस किए गए, वह गुजरात के किसानों को पसंद नहीं आए: प्रवीण राम

मैं इकोजोन मुद्दे पर, घेड मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर आवाज उठाता हूं, इसी वजह से मुझे जेल में डाला गया: प्रवीण राम

जो लोग वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों में से एक पर भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई: प्रवीण राम

हडदड में भाजपा द्वारा किया गया षड्यंत्र था: प्रवीण राम

मैंने किसानों से बैठकर रहने को कहा और शांति की अपील भी की: प्रवीण राम

जिन लोगों ने हमें जेल में डाला, उन्होंने हमें और मजबूत किया: प्रवीण राम

घेड और किसानों सहित पिछली सभी लड़ाइयां फिर से शुरू होंगी: प्रवीण राम

अहमदाबाद/जूनागढ़/सुरेंद्रनगर/बोटाद/राजकोट/अमरेली/देवभूमि द्वारका/गिर सोमनाथ/पोरबंदर/गुजरात

आम आदमी पार्टी के किसान नेता और फ्रंटल संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण राम 108 दिनों की जेलवास के बाद बाहर आए हैं और किसानों सहित पूरे गुजरात के लोगों के लिए अपनी मजबूत आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया के साथ किसान नेता प्रवीण राम ने आज केशोद में 'किसान संवाद' कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, किसान, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि आजादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेज भी भाजपा नेताओं की तरह ही सोचते होंगे कि 'अगर आजादी की बात लेकर निकलने वालों को जेल में डाल दिया जाए तो आजादी की बात ही बंद हो जाएगी।' इसी सोच के साथ अंग्रेजों ने हमारे देश के कई महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाला, फिर भी आजादी आई। भाजपा नेताओं को भी यह भ्रम है कि अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देंगे तो गुजरात में भाजपा ही चलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप एक प्रवीण राम को जेल में डालोगे तो 500 प्रवीण राम तैयार होंगे, अगर आप एक राजू करपड़ा को जेल में डालोगे तो 500 राजू करपड़ा तैयार होंगे।

आगे विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि अब तक भाजपा और कांग्रेस के नेता एक-दूसरे का काम करते थे और अंदरखाने पार्टी बदलते रहते थे, जिसके कारण जनता का कोई काम नहीं होता था। उन्होंने कभी भी गुजरात के आम लोगों और खासकर किसानों की आवाज नहीं सुनी। लेकिन अब गुजरात में और देश में आम आदमी पार्टी खड़ी हुई और एक तरफ से ईसुदानभाई आए, एक तरफ से मैं आया, एक तरफ से प्रवीणभाई आए, एक तरफ से चैतरभाई आए और इस तरह कई लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े और भगवान के आशीर्वाद से गुजरात में आम आदमी पार्टी का मजबूत काम हुआ। इसलिए पूरे गुजरात की उम्मीद और भरोसा आम आदमी पार्टी पर टिका है। अब तक भाजपा को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब पहली बार भाजपा के सामने खड़े होने वाले युवा मैदान में आए हैं और इसी वजह से भाजपा वाले परेशान हो गए हैं। और अगर आगे भी गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिला तो भाजपा वाले हाथ में भी नहीं आएंगे।

इसके बाद आम आदमी पार्टी के किसान नेता प्रवीण राम ने अपने संबोधन में कहा कि 108 दिनों की जेलवास के दौरान केशोद की जनता सहित पूरे गुजरात की जनता ने जिस तरह मुझे और मेरे परिवार को समर्थन दिया, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। हम पर जो झूठे केस किए गए, वह गुजरात के किसानों को पसंद नहीं आए। मुझे किसी व्यक्तिगत लड़ाई के कारण जेल में नहीं डाला गया, बल्कि मैं इकोजोन की लड़ाई लड़ता हूं, घेड मुद्दे पर लड़ाई लड़ता हूं, किसानों की आवाज उठाता हूं, इसी वजह से मुझे जेल में डाला गया। उन्हें लगा कि हमें जेल में डालकर वे हमें कमजोर कर देंगे, लेकिन मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हमें जेल में डालकर आप लोगों ने हमें और मजबूत किया है और भगवान करे कि आप लोग सौ साल जिएं।

इसके बाद किसान नेता प्रवीण राम ने हडदड में हुई घटना के बारे में बात करते हुए कहा कि हडदड गांव में मैंने अपनी बात पूरी की और राजूभाई करपड़ा ने भी अपनी बात पूरी की और बस कार्यक्रम खत्म होने ही वाला था। उसी समय पुलिस आती है और मैंने किसानों से बैठकर रहने को कहा तथा शांति की अपील की। लेकिन पुलिस वापस चली जाती है और कुछ मिनट बाद फिर लौट आती है और हमने फिर से लोगों से बैठने की अपील की। तीसरी बार जब पुलिस आई तो हेलमेट और लाठियों के साथ आई। इसके बाद पुलिस भीड़ में घुस गई। वहां जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनकी विवेकबुद्धि कहां चली गई? क्या पुलिस ने उकसाया नहीं? और भी गंभीर बात यह है कि जिन लोगों को उन्होंने भेजा, उनमें से कुछ ने पत्थरबाजी की, जिनमें भाजपा के लोग भी थे। इस पूरी घटना के बाद जिन 85 लोगों पर पुलिस शिकायत दर्ज की गई, उनमें से एक भी व्यक्ति पत्थर फेंकता हुआ नहीं था। इन 85 लोगों के पत्थर फेंकने का एक भी वीडियो पुलिस के पास नहीं था, तो फिर पुलिस ने इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया? दूसरी चौंकाने वाली बात यह है कि जो लोग वीडियो में पत्थर फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन पर एक भी पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने बजट 2026 को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट बताया

युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बिजनेस शुरू करने और नौकरियां पैदा करनें के लिए दस हजार करोड़ रुपए का एक अलग फंड तैयार किया हैझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

यह बजट केवल पांच वर्ष के लिए सोचकर नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया हैझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

बजट 2026 इज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेल, स्वास्थ्य, युवा, कृषि, हवाई सेवा, गांव गरीब, किसान आदि सभी क्षेत्रों को गति देगाझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ भविष्य की एआई की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया हैझकेंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान

(जीएनएस)।

वाराणसी। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने आज वाराणसी में पत्रकारों के साथ केंद्रीय बजट 2026झ27 पर चर्चा की। सर्किट हाउस के सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बजट 2026 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा और मध्यम वर्ग सबके सशक्तिकरण का रोड मैप है।

इस बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत निवेश को नई उचाई दी गई है और इससे सरकार ने साफ संदेश दिया है कि भारत अब रूकने वाला नहीं है, बल्कि तेज गति से आगे बढ़ने वाला राष्ट्र है। इससे बड़े पैमानें पर रोजगार पैदा होगा और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने देश को आधुनिक बनाने के लिए 12.2 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) और 53 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट दिया है, जिससे शानदार सड़कें एवं पुल बनेंगे। विदेश पढ़ने जाने वाले बच्चों और इलाज कराने वालों के लिए टीसीएस टैक्स को 5% से घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कैंसर की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला टैक्स (कस्टम ड्यूटी) पूरी तरह माफ कर दिया है, जिससे गरीबों का इलाज सस्ता होगा। देश की हर बेटी सुरक्षित माहौल में पढ़ सके, इसके लिए बजट में हर जिले में एक "गर्ल्स हास्टल" बनाने का वादा किया गया है। साथ ही गांव कि महिलाओं के बनाए सामान को शहर और दुनिया में बेचने के लिए शी-मार्ट खोले जायेंगे।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने बताया कि पूणे और दिल्ली-वाराणसी जैसे शहरों के बीच 7 नई हाई-स्पीड रेल लाइन बिछाई जाएंगी, जिससे सफर का समय काफी कम हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों कि तरक्की को भी वरीयता दी गई है। हमारे किसानों के काजू और नारियल को अब पूरी दुनिया में एक "बड़े ब्रांड" की तरह बेचा जाएगा, जिससे उनकी जेब में ज्यादा पैसा आएगा। इसके साथ ही हमारे मछुआरे भाई अब समुद्र में जो भी मछली पकड़ेंगें उस पर उन्हें कोई टैक्स या ड्यूटी नही देनी पड़ेगी।

युवाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नए बिजनेस शुरू करने और नौकरियां पैदा करनें के लिए दस हजार करोड़ रुपए का एक अलग फंड तैयार किया है। कॉलेज से निकलने वाले युवाओं को तुरंत नौकरी मिले, इसके लिए "करपोरेट मित्र" ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत दुनिया का टेक-गुरू बने, इसके लिए 40 हजार करोड़ रुपए सिर्फ चिप और सेमीकंडक्टर बनानें के लिए दिए गए हैं।

छोटे उद्योगो को सहारा देने के उद्देश्य से पुरानें और बंद पड़े कारखानों को फिर से चालू करने के लिए 200 पुराने औद्योगिक इलाकों को नया जीवन दिया जाएगा।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि दुनिया भर में मंदी है, लेकिन भारत ने अपने घाटे को 4.3% पर रोककर यह दिखा गया है कि हमारी अर्थव्यस्था चट्टान कि तरह मजबूत है।

उन्होंने बताया कि देश में 5 बड़े मेडिकल हब बनाए जाएंगे, ताकि दुनिया भर के लोग भारत में इलाज कराने आएं और यहां रोजगार बढ़े।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में रक्षा बजट 6.22 लाख करोड़ था, जिसको सरकार ने इस बार 26% बढाकर 7.84 लाख करोड़ किया है।

उन्होंने आगे कहा कि यह बजट केवल पांच वर्ष के लिए सोचकर नहीं है, बल्कि 2047 के विकसित भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया किया गया है। यह बजट इज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेल, स्वास्थ्य, युवा, कृषि, हवाई सेवा, गांव गरीब, किसान आदि सभी क्षेत्रों को गति देगा।

श्री कमलेश पासवान ने कहा कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ भविष्य की एआई की जरूरतों को भी ध्यान में रखा गया है। इसके लिए 40000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य की तैयारी के तहत मोबाइल और बैटरी बनाने के लिए जरूरी खनिजों के लिए ओडिसा और दक्षिण भारत में "स्पेशल कॉरिडोर" बनाए जाएंगे।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीण विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह बजट ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

RNI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

देशहित के मुद्दों पर राजनीतिक दलों के मध्य बंद है बातचीत

राजनीति का गिरता स्तर, अंकुश कौन लगाए, राजनीति के गिरते स्तर के चुनिन्दा उदाहरण मात्र हैं। पिछले कई वर्षो से देश में मिल-बैठकर देश की समस्याओं महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिचाई आदि पर राजनीतिक दलों में कोई बात नहीं हो रही है। राजनीति का गिरता स्तर, अंवुश कौन लगाए वैसे तो राजनीति का अभिप्राय राजकाज चलाने वाली नीति से है। इसका एकमात्र मकसद समतामूलक सुसय समाज का निर्माण करना और देश के चहुंमुखी विकास में योगदान देना है। लेकिन दुर्भाग्य से अपने देश में राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। यह क्षरण कहां जाकर थमेगा, पुख्ता तौर पर कोई नहीं कह सकता। यह गिरावट एक दिन में नहीं आयी है। आजादी के बाद हमारे संविधान निमार्ताओं और नीति नियंताओं ने काफी सोचवि चार कर समाज और देश के विकास का सपना देखा था। तब हमारी गिनती एक लुटे-पिटे गरीब देशों में होती थी। आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होने का दावा करते हैं, लेकिन नैतिक तौर पर तेजी से पाताल की ओर गिरते जा रहे हैं। पिछले दिनों संसद के भीतरबाहर जो वुछ भी घटित हुआ, उससे हमारा लोकतंत्र और ज्यादा शर्मसार हुआ है। संसद के बाहर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने एक केन्द्रीय मंत्री को 'गद्दार दोस्त' कहकर पुकारा तो बदले में मंत्री ने उन्हें 'देश का दुश्मन' कह दिया। दोनों नेता कभी एक ही पाटा में साथ रह चुके हैं। दोनों के पुरखों का देश के विकास में योगदान रहा है। बात इतने में थम जाती तो गनीमत थी। लोग बाग मान लेते कि हम उम्र होने के कारण दोनों ने मजाक में वुछ बोल दिया। बात बराबर। लेकिन यह क्या? संसद में इस बात को लेकर बतंगड़ बना दिया गया। इसे समुदाय विशेष की अस्मिता से जोड़ दिया गया, खूब हंगामा हुआ। एक बड़बोले सांसद ने तो नेता प्रतिपक्ष को 'फटीचर' तक कह दिया। बेशक, तीनों ही शब्द माननीयों की गरिमा को गिराते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब दूसरी घटना। लगभग 22 वर्षो बाद संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में अपनी बात नहीं रख सके। इससे पहले 10 जून 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिह को तब के विपक्ष (अब सरकार में) के विरोध के कारण संसद में बोलने नहीं दिया गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए दोनों ही घटनाएं शर्मसार करनेवाली हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने यह बयान देकर सनसनी पैला दी कि प्रधानमंत्री तो संसद में आकर अपनी बात कहने को इच्छुक थे, उन्हें मैंने ही सदन में आने से रोक दिया, क्योंकि उनके साथ वुछ अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। सवाल उठता है कि क्या भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद में हमारे प्रधानमंत्री असुरक्षित हैं? अगर, वाकई यह बात सही है तो बहुत ही दुखदाई है। प्रधानमंत्री को किससे सुरक्षा का खतरा है? संसद में तो जनता द्वारा चुने गए सांसद बैठते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष के बुलाने पर मार्शल आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को इसका खुलासा करना चाहिए। घटना की नामजद एफआईआर करानी चाहिए और नामजद व्यक्ति अगर संसद का सदस्य है तो उसकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और अगर यह बात सही नहीं है तो लोकसभा अध्यक्ष को अपने कहे के लिए देश से तत्काल माफी मांगनी चाहिए। अगर, देश के प्रधानमंत्री अपनी ही संसद में असुरक्षित हैं तो फिर देश में सुरक्षित कौन है? गृहमंत्री क्या कर रहे हैं? हमारी सुरक्षा एजेंसियां किसके आदेश का इंतजार कर रही हैं? दरअसल, लोकसभा में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले विपक्ष की वुछ महिला सांसद वेल में पहुंच गयी थीं, वुछ प्रधानमंत्री के बैठने के स्थान के बाहर खड़ी थीं। उनके हाथ में तख्ती थी। यह कोई नई बात नहीं है। अपनी बात मनवाने अथवा अध्यक्ष का ध्यान आर्कषित करने के लिए सांसद अकसर वेल में पहुंचते रहते हैं। वे अपनी बात की तख्ती लिये विरोध भी करते रहे हैं। इससे वे अपराधी नहीं बन जाते। सांसद भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और

संयुक्त राज्य अमेरिका-भारत का संयुक्त वक्तव्य

(जीएनएस)।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वे पारस्परिक और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते (अंतरिम समझौता) के ढांचे पर सहमत हो गए हैं। आज का यह ढांचा 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए व्यापक अमेरिका-भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) वार्ता के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है जिसमें अतिरिक्त बाजार पहुंच प्रतिबद्धताएं शामिल होंगी और अधिक लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यह अंतरिम समझौता हमारे देशों की साझेदारी में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। यह समझौता पारस्परिक हितों और ठोस परिणामों पर आधारित पारस्परिक और संतुलित व्यापार के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दशार्ता है।

अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित होंगी:

भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों और अमेरिकी खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ को समाप्त या कम करेगा। इसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन्स (डीडीजी), पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट तथा अन्य उत्पाद शामिल हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 अप्रैल, 2025 के कार्यकारी आदेश 14257 (बड़े और लगातार वार्षिक अमेरिकी माल व्यापार घाटे में योगदान देने वाली व्यापार प्रथाओं को सुधारने के लिए पारस्परिक टैरिफ के साथ आयातों को विनियमित करना), यथा संशोधित, के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं पर 18 प्रतिशत की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा, जिसमें वस्त्र और परिधान, चमड़ा और जूते, प्लास्टिक और रबर, जैविक रसायन, घरेलू सजावट, हस्तशिल्प उत्पाद और कुछ मशीनरी शामिल हैं, और अंतरिम समझौते के सफल समापन के अधीन, 5 सितंबर, 2025 के कार्यकारी आदेश 14346 (पारस्परिक टैरिफ की सीमा को संशोधित करना और व्यापार और सुरक्षा समझौतों को लागू करने के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना करना), यथा कि संशोधित किया गया है, के अनुरूप भागीदारों के लिए संभावित टैरिफ समायोजन अनुबंध में पहचानी गई वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर पारस्परिक टैरिफ हटा देगा। इसमें जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और हीरे और विमान के पुर्जे शामिल हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के कुछ विमानों और विमान पुर्जों पर लगाए गए उन टैरिफ को भी हटा देगा। यह टैरिफ 8 मार्च, 2018 की उद्घोषणा 9704 (संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्युमीनियम के आयात को समायोजित करना), संशोधित रूप में; 8 मार्च, 2018 की उद्घोषणा 9705 (संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के आयात को समायोजित करना), यथा संशोधित; और 30 जुलाई, 2025 की उद्घोषणा 10962 (संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे के आयात को समायोजित करना) में उल्लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को समाप्त करने के लिए लगाए गए थे। इसी प्रकार, अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत को उन ऑटोमोबाइल पुर्जो के लिए अधिमान्य टैरिफ दर कोटा प्राप्त होगा जिन पर 17 मई, 2019 के उद्घोषणा 9888 (संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पुर्जों के आयात को समायोजित करना), यथा संशोधित उल्लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों को समाप्त करने के लिए टैरिफ लागू था। फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्युटिकल अवयवों की अमेरिकी धारा 232 जांच के निष्कर्षों के आधार पर, भारत को जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और अवयवों के संबंध में बातचीत के माध्यम से समाधान प्राप्त होंगे।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक दूसरे को अपने-अपने हित के क्षेत्रों में निरंतर आधार पर वरीयता बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ऐसे निर्माण नियम बनाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि समझौते के लाभ मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत को ही प्राप्त हों।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली गैर-टैरिफ बाधाओं का समाधान करेंगे। भारत अमेरिकी चिकित्सा उपकरणों के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने; अमेरिकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) वस्तुओं के लिए बाजार पहुंच में देरी करने या उन पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने वाली प्रतिबंधात्मक आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को समाप्त करने; और समझौते के लागू होने के छह महीने के भीतर, सकारात्मक परिणाम की दिशा में, यह निर्धारित करने पर सहमत है कि क्या अमेरिकी-विकसित या अंतर्राष्ट्रीय मानक, जिनमें परीक्षण आवश्यकताएं भी शामिल हैं, भारतीय बाजार में प्रवेश करने वाले अमेरिकी निर्यात के लिए चिन्हित क्षेत्रों में स्वीकार्य हैं। लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को दूर करने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को समझते हुए, भारत अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों के व्यापार में लंबे समय से चली आ रही गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने पर भी सहमत है।

लागू तकनीकी विनियमों के अनुपालन को सुगम बनाने के उद्देश्य से, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत पारस्परिक रूप से सहमत क्षेत्रों के लिए अपने-अपने मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं पर चर्चा करेंगे।

किसी भी देश द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत इस बात पर सहमत हैं कि दूसरा देश अपनी प्रतिबद्धताओं में परिवर्तन कर सकता है।

अलवर में 'बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों का सम्मेलन

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने राजस्थान के अलवर में 'बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों के सम्मेलन' की अध्यक्षता की

बाघों के प्रभावी संरक्षण के लिए नीतिगत निर्णयों की व्यापक समीक्षा और क्षेत्रवार चुनौतियों की पहचान आवश्यक है: श्री भूपेंद्र यादव

(जीएनएस)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने शनिवार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की अब तक हुई 28 बैठकों में लिए गए सभी नीतिगत निर्णयों की समीक्षा के लिए सम्मेलन बुलाया ताकि उन निर्णयों की पहचान की जा सके जो अप्रचलित हो चुके हैं, जिन्हें लागू नहीं किया जा सका है और जिन्हें पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इस पहल से बाघ संरक्षण नीति को वर्तमान समय की चुनौतियों के अनुरूप ढालने और जमीनी स्तर पर संरक्षण उपायों के कुशल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

राजस्थान के अलवर में आयोजित 'बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों के सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मंत्री यादव ने कहा कि भारत ने बाघ संरक्षण के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह व्यापक नीति समीक्षा का उपयुक्त समय है। दो दिवसीय सम्मेलन की दिशा तय करते हुए श्री यादव ने सुझाव दिया कि पिछले पांच दशकों में लिए गए नीतिगत निर्णयों को एक औपचारिक नीतिगत वक्तव्य में संकलित किया जाना चाहिए और इस मुद्दे को एनटीसीए की अगली बैठक के पहले एजेंडा आइटम के रूप में रखा जाना चाहिए।

इस सम्मेलन में राजस्थान सरकार के वन मंत्री श्री संजय शर्मा के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एनटीसीए के वरिष्ठ अधिकारी, बाघ रेंज राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन और देश भर के बाघ अभ्यारण्यों के फील्ड निदेशकों ने भाग लिया।

श्री यादव ने कहा कि बाघों की संख्या का आकलन, बचाव एवं पुनर्वास संबंधी बुनियादी ढांचा,

मानव-वन्यजीव संघर्ष, बाघ अभ्यारण्य निधि का उपयोग और बाघ संरक्षण की नींव को मजबूत करने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श आवश्यक है। सम्मेलन में देश में बाघ संरक्षण की समग्र स्थिति की समीक्षा की जाएगी और प्रमुख नीतिगत, प्रबंधन और परिचालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।

श्री यादव ने बाघों की संख्या में बदलाव सहित क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों की समीक्षा करने और देश के बाघ अभ्यारण्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए चार कार्य समूहों के गठन का भी आह्वान किया। इसके अलावा, मंत्री ने प्रतिभागियों से एनटीसीए और भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जैसे संस्थानों के बीच समन्वय बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने को भी कहा ताकि इन शीर्ष संगठनों से प्राप्त शोध सुझावों को शामिल किया जा सके और बाघ संरक्षण में व्यावहारिक लाभ प्राप्त किए जा सकें।

चीता पुनर्वास कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए मंत्री जी ने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक एक ऐसी जंगली प्रजाति का अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण किया है जो देश में विलुप्त हो चुकी थी, और यह परियोजना अब चीतों की तीसरी भारतीय पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि बोत्सवाना से चीतों का एक नया समूह फरवरी के अंत तक आने की उम्मीद है।

श्री यादव ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना की है, जिसमें अब तक 24 सदस्य देश हैं, जबकि कई अन्य देशों ने पर्यवेक्षक का दर्जा मांगा है। उन्होंने कहा कि यूएनडीपी, आईयूसीएन, एफएओ, सीसीएफ, जीटीएफ और जीएसएलईपी जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी आईबीसीए के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट में घोषणा की गई है कि पहला वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आईबीसीए के माध्यम से तीन प्रमुख वैश्विक चुनौतियों – बढ़ती गर्मी, भूमि का मरुस्थलीकरण और जैव विविधता का नुकसान – का समाधान किया जा सकता है।

मंत्री जी ने कहा कि बाघों और अन्य वन्यजीवों के निर्धारित क्षेत्रों से बाहर निकलने के कारण मजबूत प्रतिक्रिया प्रणालियों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि घायल जानवरों, संघर्ष से संबंधित मामलों, अनाथ शावकों और तनावग्रस्त अन्य जानवरों को समय पर और पेशेवर सहायता की आवश्यकता होती है, इसलिए बाघ अभ्यारण्यों के आसपास बचाव, पुनर्वास और उपचार केंद्रों के लिए एक स्पष्ट और मानकीकृत ढांचा विकसित करना आवश्यक है। इस अवसर पर मंत्री जी ने एनटीसीए की प्रचार पत्रिका –

भारत के खिलाफ मैच खेलने के बदले पाकिस्तान ने मांगीं ये तीन रियायतें, मैच पर सस्पेंस बरकरार

(जीएनएस)।

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को होने वाले भारत-पाकिस्तान मुकाबले को लेकर सस्पेंस बरकरार है। पाकिस्तान सरकार द्वारा मैच के बहिष्कार की घोषणा के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस फैसले पर यू-टर्न लेने के संकेत दिए हैं। हालांकि, इसके लिए बोर्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सामने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं।

आखिर कैसे शुरू हुआ था पूरा विवाद

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान सरकार ने टूनार्मेंट में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने के आईसीसी के फैसले के विरोध में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का ऐलान किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की इस घोषणा के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को गंभीर परिणामों की चेतावनी दी थी। अब टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार, पीसीबी इन शर्तों के आधार पर मैच खेलने को तैयार हो सकता है।

पाकिस्तान ने रखी ये मांग

पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी मांग आईसीसी के वार्षिक राजस्व पूल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की है। वर्तमान में पीसीबी को 34.5 मिलियन डॉलर मिलते हैं। बोर्ड का तर्क है कि भारत-पाकिस्तान मुकाबले आईसीसी के लिए सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करते हैं, इसलिए उन्हें मिलने वाली फंडिंग में भी उसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी चाहिए। पीसीबी सूत्रों के अनुसार, वे इस डेडलॉक का इस्तेमाल एक बेहतर सौदेबाजी के लिए कर रहे हैं।

भारत के साथ खेलने

पीसीबी ने आईसीसी से मांग की है कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के साथ मध्यस्थता करे ताकि दोनों देशों के बीच रुकी हुई द्विपक्षीय सीरीज फिर से शुरू हो सके। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच 2013 के बाद से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। हालांकि, इस मांग का पूरा होना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बीसीसीआई का रुख हमेशा स्पष्ट रहा है कि द्विपक्षीय क्रिकेट का फैसला पूरी तरह भारत सरकार के हाथ में है।

मैदान पर खेल भावना का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने मांग की है कि भारतीय खिलाड़ी मैच के दौरान पारंपरिक रूप से हाथ मिलाने की

ब्लैक गॉगल्स, ब्लू शर्ट पहन आरएसएस के प्रोग्राम में सलमान खान ने की शानदार एंट्री, सब रह गए दंग

(जीएनएस)।

मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष समारोह में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की उपस्थिति ने सबको चौंका दिया। कार्यक्रम स्थल पर जैसे ही 'भाईजान' पहुंचे, सभी कैमरों का ध्यान तुरंत उनकी ओर मुड़ गया और वे मुख्य आकर्षण का केंद्र बन गए। यह भव्य आयोजन संघ के गौरवशाली सौ वर्षों के सफर का जश्न मना रहा है। इस कार्यक्रम में शाहरुख खान और आमिर खान को भी निमंत्रण भेजा गया था।

सलमान खान की एंट्री काफी शानदार रही, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में वह अपनी चिर-परिचित शैली में गहरे नीले रंग की शर्ट और आंखों पर चश्मा लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत का संबोधन होगा, जिसमें वे आरएसएस के सौ साल के ऐतिहासिक कार्यकाल पर प्रकाश डालेंगे।

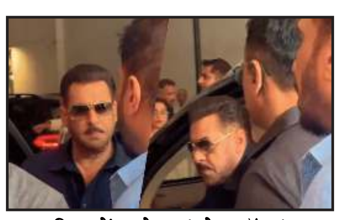

मुंबई के नेहरू सेंटर में RSS द्वारा 'नवे क्षितिज' नामक दो दिवसीय व्याख्यानमाला का उद्घाटन शनिवार को हुआ। इसमें फिल्म निमार्ता सुभाष घई, अभिनेत्री अश्विनी भावे और दिग्गज हेमा मालिनी सहित कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल थीं। हालांकि, सलमान खान की एंट्री ने सबकी नजरों में उन्हें कार्यक्रम का 'शो स्टॉपर' बना दिया।

इस कार्यक्रम में कई फिल्मी हस्तियां उपस्थित थीं लेकिन सलमान के पहुंचते ही, गणमान्य व्यक्ति और कैमरे स्वाभाविक रूप से उनकी ओर मुड़ गए, और उनकी उपस्थिति ने अनेकों की भौंहें चढ़ा दीं।

आरएसएस अपने 100 वर्ष पूरे कर रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार द्वारा स्थापित किया गया था। हिंदू समाज को संगठित, अनुशासित और सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। बीते एक सदी में, संघ के सदस्यों ने समाज व देश में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किए हैं।

900 मेहमान आमंत्रित हैं

'नवे क्षितिज' व्याख्यानमाला के तहत, सरसंघचालक मोहन भागवत का विशेष व्याख्यान आज निर्धारित है।

कमल हासन की बेटी श्रुति का धर्म और भगवान पर शॉकिंग खुलासा

(जीएनएस)।

साउथ फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन की बेटी और जानी-मानी अभिनेत्री श्रुति हासन ने हिंदी, तमिल और तेलुगू सिनेमा में अपनी मेहनत से अलग पहचान बनाई है। फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद श्रुति हासन ने अपनी पहचान विरासत के सहारे नहीं बल्कि अपनी मेहनत और सोच की अलग दिशा से बनाई है।

श्रुति हासन का आस्था को लेकर शॉकिंग खुलासा

हाल ही में श्रुति हासन ने अपने बचपन, परिवार की विचारधारा और आस्था को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया है। श्रुति हासन ने बताया कि वह एक ऐसे माहौल में पली-बढ़ीं, जहां धर्म और भगवान की पारंपरिक मान्यताओं की जगह कला, तर्क और स्वतंत्र सोच को महत्व दिया जाता था।

'हमारे घर में भगवान और धर्म की कोई जगह नहीं'

एक हालिया इंटरव्यू में श्रुति हासन ने अपने बचपन, परिवार की सोच और आस्था को लेकर खुलकर बातें की हैं। उन्होंने बताया कि वह एक ऐसे घर में पली-बढ़ीं, जहां भगवान और धर्म की पारंपरिक अवधारणा का कोई स्थान नहीं था।

'हम नास्तिक परिवार में बड़े हुए हैं'

-श्रुति हासन ने बताया कि उनका परिवार खुद को नास्तिक मानता है। घर में पूजा-पाठ, व्रत या किसी खास दिन खानपान के नियम जैसी परंपराएं नहीं थीं। उनके अनुसार बचपन से ही उनके मन में ये विचार बैठ गया था कि कला ही उनकी सबसे बड़ी आस्था है।

-श्रुति हासन ने ये भी कहा कि जब वह इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से करती हैं तो उनके पिता कमल हासन को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वह धर्म पर चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं।

भाषा, स्कूल और अलग तरह का बचपन

-श्रुति हासन ने बताया कि वह तमिल और हिंदी माहौल के बीच पली-बढ़ी हैं। घर में अक्सर हिंदी और अंग्रेजी बोली जाती थी जबकि वह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती थीं। इसका असर ये हुआ कि लंबे समय तक उनकी तमिल काफी कमजोर रही थी।

-एक्ट्रेस ने अपने बचपन को सामान्य से अलग बताया। फिल्मों के सेट पर बड़ा होना, अलग-अलग कलाकारों से मिलना और असामान्य माहौल में रहना, ये सब उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। उन्होंने ये भी शेयर किया कि उनके माता-पिता पारंपरिक स्कूलिंग से नहीं गुजरे थे इसलिए पढ़ाई को लेकर घर का माहौल भी अलग था।

कमल हासन और ज्योतिष-टैटू पर विचार

-श्रुति हासन ने बताया कि अगर उनके पिता कमल हासन से ज्योतिष या ऐसे विषयों पर बात की जाए तो वह उसे तुरंत खारिज कर देते हैं। कमल हासन बेहद व्यावहारिक सोच रखते हैं और टैटू जैसी चीजें भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं हैं।

-जहां श्रुति हासन का परिवार पारंपरिक धर्म को नहीं मानता, वहीं एक्ट्रेस ने कहा कि वह विक्का (प्रकृति से जुड़ी आध्यात्मिक मान्यताओं) में विश्वास रखती हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें महसूस होता है कि वह एक मजबूत विरासत से जुड़ी हैं। उनके लिए प्रकृति, ऊर्जा और कला ही आध्यात्मिकता का रूप हैं।

श्रुति हासन का फिल्मी करियर

श्रुति हासन 'सालारः पार्ट 1- सीजफायर', 'गब्बर सिंह', 'रेस गुर्रम', 'श्रीमान्थुडु' और 'रमैया वस्तावैया' जैसी दमदार फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अपने दम पर बनाई पहचान के साथ वह आज भी सिनेमा में काफी एक्टिव हैं। श्रुति की बातें ये दिखाती हैं कि हर कलाकार की सोच और परवरिश अलग हो सकती है और वही विविधता उन्हें खास बनाती है।

गिरफ्तारी के बाद पटना मेडिकल कॉलेज गए सांसद पप्पू यादव, क्या है 1995 का पूरा विवाद?

(जीएनएस)।

करीब 35 साल पुराने एक मामले ने एक बार फिर बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को बिहार पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (PMCH) लाया गया, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद पप्पू यादव को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है, उसकी जड़ें साल 1995 से जुड़ी हैं।

यह मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में दर्ज एक एफआईआर से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 468 (जालसाजी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120इ (आपराधिक साजिश) के तहत केस दर्ज है।

गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को सुरक्षा घेरे में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाया गया। इस दौरान अस्पताल परिसर में पुलिस बल की भारी तैनाती देखने को मिली। ढटउ्र के अधीक्षक डॉ. राजीव कुमार सिंह ने मीडिया को बताया, हमने यह उचित नहीं समझा कि वार्ड के अंदर जाकर मेडिकल प्रक्रिया की जाए, क्योंकि इससे अन्य मरीजों को परेशानी हो सकती थी। पप्पू यादव का अल्ट्रासाउंड किया जा रहा है और सभी जरूरी मेडिकल जांच की जा रही हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मेडिकल जांच पूरी तरह नियमों के तहत की जा रही है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, वर्ष 1995 में पप्पू यादव और उनके करीबी लोगों ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के जरिए उनका मकान किराए पर लिया था। आरोप है कि मकान लेते समय यह बात जानबूझकर छिपाई गई कि इस आवासीय भवन का इस्तेमाल सांसद के राजनीतिक कार्यालय के रूप में किया जाएगा।

शिकायतकर्ता का कहना है कि यदि उन्हें पहले से इस बात की जानकारी होती, तो वे कभी भी अपना घर किराए पर नहीं देते। इसी आरोप के आधार पर उस समय मामला दर्ज किया गया था, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और साजिश जैसी धाराएं लगाई गईं।

मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया और अदालती सुनवाई चलती रही। हाल ही में अदालत ने पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया था, जो गिरफ्तारी से तीन दिन पहले दिया गया। इसके बाद पुलिस ने वारंट के आधार पर देर रात कार्रवाई करते हुए उनके आवास पर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

यूपी को हरा-भरा बनाने के लिए सीएम योगी का बड़ा लक्ष्य, 2030 तक हरियाली को 15 प्रतिशत करने के लिए शुरू हुई 'ग्रीन चौपाल'

लखनऊ। (जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया है। यह लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब पौधरोपण को जनांदोलन का स्वरूप दिया जा सके। सीएम के विजन को केंद्र में रखते हुए वन विभाग ने गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन करने का निर्णय किया और इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की। विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रत्येक ग्रामसभा स्तर पर ग्रीन चौपाल का गठन किया जा रहा है। अब तक 14,318 गांवों में चौपाल का गठन/आयोजन किया जा चुका है।

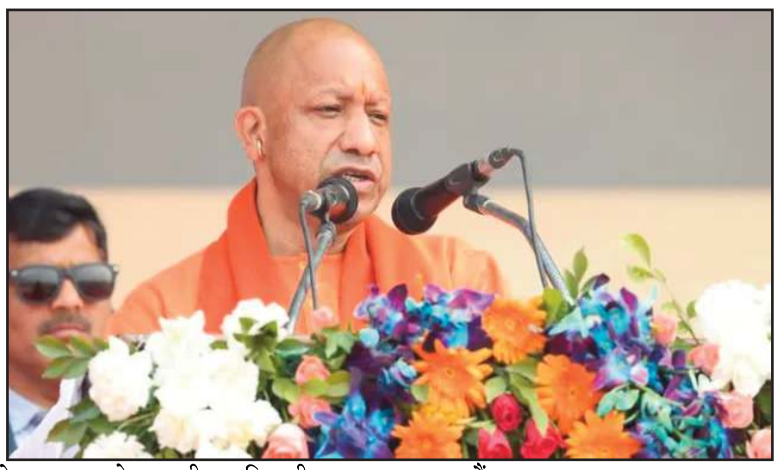

इन ग्रीन चौपालों में शामिल होने वाले लोगों से वर्ष 2026 में चलाए जाने वाले पौधरोपण अभियानों पर चर्चा करने के साथ-साथ उन्हें तैयारी से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं। ग्रीन चौपालें ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं, युवाओं, बुज़ुर्गों आदि को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही हैं।

ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष ग्राम प्रधान, सेक्शन/बीट अधिकारी सदस्य सचिव तथा ग्राम पंचायत सचिव संयोजक बनाए गए हैं। इसके अलावा तीन ग्राम पंचायत सदस्य (न्यूनतम एक महिला सदस्य), स्वयं सहायता समूह की एक महिला प्रतिनिधि, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सहायिका, प्रगतिशील कृषक, पर्यावरणविद/स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधि व जैव विविधता प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि चौपाल के सदस्य हैं।

प्रदेश की हरियाली बढ़ाने के उद्देश्यों से प्रत्येक माह ग्रीन चौपाल की कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से होनी है। इसमें विभिन्न विभागों की पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन आदि के प्रति स्थानीय स्तर पर विशेष प्रचार-प्रसार (नुक्कड़ नाटक, रैली, गोष्ठी) आदि का भी आयोजन हो रहा है। जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा ग्रीन चौपाल के कार्यों की निगरानी भी की जा रही है। प्रभागीय वनाधिकारी इसका समन्वयन कर रहे हैं।

वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रामकुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गांवों में ग्रीन चौपालें लगाई जा रही हैं। इसका उद्देश्य यूपी में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण है। इसके लिए ग्रीन चौपाल की भी मदद ली जाएगी। गांव स्तर पर प्रधान इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। प्रतिमाह ग्रीन चौपाल की कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से हो रही है। अब तक 14,318 गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन व आयोजन किया जा चुका है। उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्रीन चौपालों को चिह्नित भी किया जा रहा है।

मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी ने कर दी सीएम योगी की तारीफ, बोले- सभी समुदायों के साथ करते हैं निष्पक्ष व्यवहार

(जीएनएस)।

मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निष्पक्ष कार्यशैली और मुस्लिम समाज के लिए उनके योगदान की खुले तौर पर सराहना की. उनके इस बयान से राजनीतिक और सामाजिक हलचलों में चर्चा शुरू हो गई.

यूपी टॉक के खास शो 'आज का यूपी' में आज राज्य की राजनीतिक और सामाजिक हलचलों पर चर्चा हुई. इस बार चर्चा का मुख्य केंद्र बने ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, जिन्होंने अपने बयान से सबका ध्यान खींचा. अक्सर सरकार की आलोचना करने वाले मौलाना ने इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की खुले तौर पर सराहना की है.

मौलाना रजवी ने योगी की सराहना की

बता दें कि उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का कोई 'एंटी-मुस्लिम' एजेंडा नहीं है और वे सभी समुदायों के प्रति निष्पक्ष हैं. यही नहीं, मौलाना ने यूपी की स्थिति की तुलना असम और उत्तराखंड से करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था का लाभ मुस्लिम समुदाय को भी बराबरी से मिल रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी की लोकप्रियता और स्वीकार्यता मुस्लिम समाज में लगातार बढ़ रही है.

इसके अलावा, मौलाना रजवी ने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली में निष्पक्षता और विकास के प्रयास स्पष्ट रूप से दिखते हैं. उनका मानना है कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम समाज के लिए भी बेहतर विकल्प साबित हो रहे हैं. मौलाना रजवी का यह बयान राजनीतिक और सामाजिक हलचलों में चर्चा का विषय बन गया है.

पूरनपुर,तहसील में 'संपूर्ण समाधान दिवस' की बड़ी सफलताः एडीएम व एडिशनल एसपी ने सुनीं 50 से अधिक शिकायतें, तत्काल निस्तारण के आदेश

(जीएनएस)।

पीलीभीत(पूरनपुर)में शुक्रवार को आयोजित 'संपूर्ण समाधान दिवस' के अवसर पर अपर जिलाधिकारी (अञ्ट) एवं एडिशनल एसपी ने आमजन की विभिन्न समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनने के साथ ही उनका त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए। इस एकल दिवसीय कार्यक्रम में 50 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से अधिकांश को स्थानीय स्तर पर ही हल करने के आदेश दिए गए। प्रशासन की इस सक्रियता से क्षेत्रवासियों में उत्साह का संचार हुआ है।

तहसील सभागार में सुबह 10 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में अञ्ट ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक फरियादी से उनकी समस्या सुनी। शिकायतों में मुख्य रूप से राजस्व विभाग से जुड़े भूमि विवाद, नामांतरण, खसरा-खतौनी सुधार शामिल थे। इसके अलावा, बिजली विभाग की अनियमित आपूर्ति, पीडीएस राशन वितरण में गड़बड़ी, पेयजल संकट तथा ग्रामीण सड़कों की खराब स्थिति जैसी समस्याएं प्रमुख रहीं। एक बुजुर्ग किसान रामस्वरूप ने बताया, "हमारी 2 एकड़ जमीन का नामांतरण 6 माह से लंबित था। आज अञ्ट साहब ने तहसीलदार को 7 दिनों में पूरा करने का आदेश दिया। अब न्याय मिलने की उम्मीद है।

"एडिशनल एसपी ने कानून-व्यवस्था से संबंधित शिकायतों पर विशेष फोकस किया। चोरी, घरेलू हिंसा, अवैध शराब बिक्री तथा ट्रैफिक व्यवस्था की समस्याओं पर थाना प्रभारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "पुलिस का द्वार हर नागरिक के लिए खुला है। ऐसी शिकायतों का 15 दिनों में निस्तारण अनिवार्य होगा, वरना विभागीय जांच होगी।" कार्यक्रम में दर्ज शिकायतों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया गया, ताकि फरियादी घर बैठे स्टेटस ट्रैक कर सकें।

अञ्ट ने समापन सत्र में अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश सरकार की 'संपूर्ण समाधान' योजना का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों तक न्याय पहुंचाना है। पीलीभीत जिले में अब तक 500 से अधिक शिकायतें निस्तारित हो चुकी हैं। पूरनपुर तहसील में अगला आयोजन 20 फरवरी को निर्धारित है।" कार्यक्रम में तहसीलदार संजय कुमार, बीडीओ राकेश सिंह, एसडीएम प्रतिनिधि तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

इस पहल से न केवल जनता का प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने में भी सहायता मिल रही है। स्थानीय सामाजिक कार्यकताओं ने इसे 'लोकतंत्र की सच्ची जीत' बताते हुए सराहना की। जिला प्रशासन ने घोषणा की कि ऐसी सुनवाई अब प्रत्येक तहसील में मासिक आधार पर आयोजित होगी।

भारतीय किसान यूनियन भानू ठाकुर हर्ष सिंह जी को छात्र संघ जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष मसौली मोहम्मद आरिफ जी ब्लॉक महामंत्री बलजीत जी को नियुक्त किया गया

(जीएनएस)।

भारतीय किसान यूनियन भानू संगठन जो किसानों गरीबों मजदूरों की लड़ाई मजबूती से लड़ता चला आ रहा है परंतु विगत कुछ महीनो से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संगठन को बदनाम एवं व्यक्तिगत लाभ के लिए संगठन की गरिमा को तार-तार करने एवं संगठन में अनुशासनहीनता फैलाने का काम किया है ,इसलिए संगठन को सही दिशा एवं शांति व्यवस्था को स्थापित करने हेतु आज दिनांक 7.2.2026 दिन शनिवार को मंडल कार्यालय पटेल बाराबंकी पर पूजन हवन एवं भंडारे का आयोजन किया गया । पूजा अर्चना के उपरांत संगठन के प्रदेश महासचिव रणवीर सिंह जी , मंडल अध्यक्ष अयोध्या रवि वर्मा जी , युवा मंडल अध्यक्ष सोनू शर्मा जी , एवं जिलाध्यक्ष बाराबंकी देशराज वर्मा जी एवं सभी सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा एक बैठक की गई और संगठन हित में ठोस निर्णय लिया गया , जिसमें यदि भविष्य में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा संगठन का नाम एवं झंडा बैनर उपयोग किया जाता है तो संगठन द्वारा उनके ऊपर विधिक कार्यवाही

लगातार संगठन में अशांति एवं अनुशासनहीनता कर रहे मंडल अध्यक्ष छात्र संघ आशीष यादव , जिलाध्यक्ष छात्र संघ अर्पित राठौर एवं ब्लॉक अध्यक्ष मसौली राहुल गुप्ता को तत्काल प्रभाव से पद मुक्त करते हुए देवा ब्लॉक की पूरी कार्यकारणी को भंग किया गया , की जाएगी , इसके पश्चात कुछ नए सदस्यों को संगठन की नई जिम्मेदारी दी गई जो इस प्रकार है सिद्धांत सिंह जी को मंडल अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ एवं ठाकुर हर्ष सिंह जी को छात्र संघ जिला अध्यक्ष बाराबंकी और ब्लॉक अध्यक्ष मसौली मोहम्मद आरिफ जी ब्लॉक महामंत्री बलजीत जी को नियुक्त किया गया ,

जिला अध्यक्ष बाराबंकी देशराज वर्मा ने समस्त पदाधिकारियों के सम्मुख आश्वस्त किया कि जनपद बाराबंकी के सभी तहसील और ब्लॉक की कार्यकारणी को बहुत जल्द और मजबूज किया जाएगा , और सदस्यता अभियान पूरे जिले में और तेजी से चलाया जाएगा , और भारतीय किसान यूनियन भानू का नाम पूरे जिले में सबसे ऊपर करने का कार्य किया जाएगा !!

गैंगस्टर एक्ट में 3 दोषियों को 5-5 वर्ष की सजा, 30 हजार रुपये जुमार्ना

(जीएनएस)।

पीलीभीत। पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। थाना माधोटांडा क्षेत्र से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के एक पुराने मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई है।

पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ह्वऑपरेशन कन्विक्शनह्व अभियान के अंतर्गत वर्ष 2014 में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 801/2014, धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना माधोटांडा में पंजीकृत किया गया था। इस मामले की गहन विवेचना के बाद पुलिस ने पर्याप्त साक्ष्य और सुदृढ़ पैरवी के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय अरख गैंगस्टर एक्ट/पॉक्सो-1, पीलीभीत में हुई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दिनांक 07 फरवरी 2026 को तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाया।

दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में—

1. मेहदान शाह पुत्र वजीर शाह
2. उस्मान शाह पुत्र सुमान शाह
3. फुरकान शाह पुत्र कुन्दन शाह

निवासीगण गुलाबटांडा, थाना माधोटांडा, जनपद पीलीभीत शामिल हैं।

न्यायालय ने तीनों दोषियों को धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत 5-5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 30,000 रुपये के अर्थदंड का आदेश भी दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक ने इस कार्रवाई को अपराधियों के विरुद्ध सख्त संदेश बताते हुए कहा कि भविष्य में भी संगठित अपराध के खिलाफ इसी तरह प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी।

पीलीभीत में सड़क पर गोवंश के अवशेष मिलेः पिपरिया-सुआबोझ मार्ग पर हड़कंप, बजरंग दल ने आंदोलन की चेतावनी दी

(जीएनएस)।

पीलीभीत,जिले के पूरनपुर क्षेत्र में पिपरिया दुलई-सुआबोझ मार्ग पर सड़क किनारे गोवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार देर रात खेत के पास प्रतिबंधित पशु के अवशेष पाए जाने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीणों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। राष्ट्रीय बजरंग दल और गौ रक्षा दल के कार्यकताओं ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

बजरंग दल के जिला प्रमुख ठाकुर शिवम सिंह भदौरिया ने अपनी टीम के साथ शनिवार सुबह घटनास्थल का मुआयना किया। उन्होंने आरोप लगाया कि असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र का माहौल खराब करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से यह कृत्य किया है। मीडिया से बातचीत में ठाकुर शिवम ने कहा, "गौवंश वध की घटनाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।" उन्होंने कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र सौंपा और मांग की कि दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए तथा क्षेत्र में गौ-तस्करी रोकने के लिए गश्त बढ़ाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी घटना दोबारा होने पर संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा।

पुलिस ने मामले को संवेदनशील मानते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। कोतवाली प्रभारी पवन पांडे ने बताया, "लिखित शिकायत मिल चुकी है। घटनास्थल से साक्ष्य संग्रहित किए गए हैं और जांच गहनता से चल रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। दोषी पाए जाने पर कठोरतम कार्रवाई होगी।

"क्षेत्रवासियों ने भी पुलिस से त्वरित न्याय की अपील की है। इस घटना ने स्थानीय स्तर पर तनाव बढ़ा दिया है, जिसके चलते प्रशासन सतर्क मोड में है।

बीसलपुर में गोवंश प्रबंधन को लेकर विवाद गहराया, सचिव पर मनमानी और आदेशों की अनदेखी के आरोप

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)। बीसलपुर क्षेत्र में गोवंश प्रबंधन और गौशाला संचालन को लेकर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के निर्देशों की अनदेखी तथा ग्राम सचिव अनिल पर मनमानी करने के आरोपों के बीच मामला अब प्रशासनिक जांच के दायरे में पहुंच गया है।

ग्रामीणों का आरोप है कि बीडीओ द्वारा मादा गोवंश को मिघौना क्षेत्र से खनका गौशाला भेजने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, जिनका पालन सचिव और संबंधित ग्राम प्रधान को करना था। आरोप है कि इन निर्देशों की अनदेखी की गई, जिससे अव्यवस्था फैली और गोवंशों के रख-रखाव में गंभीर लापरवाही सामने आई।

इसी बीच सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने मामले को और गरमा दिया है। वीडियो में एक ट्रॉली में बड़ी संख्या में गोवंशों को ठूंसकर ले जाते हुए दिखाया गया है। ग्रामीणों का दावा है कि ट्रॉली में करीब 12 गोवंश भरे गए थे, जिनमें दम घुटने से दो पशुओं की मौत हो गई। हालांकि, वीडियो की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि मामले में अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए कुछ अधिकारियों द्वारा भोले-भाले ग्रामीणों पर मुकदमे दर्ज कराए गए और एक अलग कहानी गढ़ी गई। उनका कहना है कि वास्तविक जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय निर्दोष लोगों को ढाल बनाया जा रहा है।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आर्थिक सांठगांठ की आशंका भी जताई है। उनका आरोप है कि गौशाला के आसपास के निराश्रित गोवंशों को संरक्षण नहीं दिया जाता, जबकि दूर-दराज गांवों से पशु लाकर गौशाला में रखे जाते हैं। इससे व्यवस्था और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।

इस पूरे प्रकरण में प्रशासन का कहना है कि मामला संज्ञान में है और वायरल वीडियो सहित सभी आरोपों की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। फिलहाल क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर जनाक्रोश और चर्चा का माहौल बना हुआ है।

पीलीभीतः वामा वेलनेस कैम्प में पुलिसकर्मियों व परिजनों को मुफ्त होम्योपैथिक परामर्श व दवा वितरण,

मासिक आयोजन से बढ़ेगी स्वास्थ्य जागरूकता

(जीएनएस)।

पीलीभीत जनपद पीलीभीत की रिजर्व पुलिस लाइन में आज वामा सारथी के तत्वावधान में आयुष विभाग की सहभागिता से वामा वेलनेस कैम्प का सफल आयोजन किया गया। इस विशेष होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों ने भाग लिया। शिविर में निःशुल्क चिकित्सीय जाँच, परामर्श एवं होम्योपैथिक दवाओं का वितरण किया गया, जिससे सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचा।आयुष विशेषज्ञों ने विभिन्न सामान्य बीमारियों जैसे सर्दी-खाँसी, पेट संबंधी विकारों, तनाव एवं जोड़ों के दर्द आदि के लिए होम्योपैथिक उपचार प्रदान किए। पुलिसकर्मियों ने बताया कि यह शिविर उनकी व्यस्त दिनचर्या में स्वास्थ्य जांच का सरल माध्यम साबित हो रहा है। वामा सारथी के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह पहल पुलिस परिवार के समग्र स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।यह मेडिकल कैम्प पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों के लिए प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को नियमित रूप से लगाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। आने वाले महीनों में अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को भी शामिल करने की योजना है, ताकि पुलिस परिवार को व्यापक लाभ मिल सके।इस आयोजन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सामुदायिक सहयोग से स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने आयुष विभाग एवं वामा सारथी का आभार व्यक्त किया है।

तहसील समाधान दिवस में पहुंचा भूमि विवाद का मामला, प्रार्थी ने कब्जे के प्रयास का लगाया आरोप

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)। बीसलपुर तहसील में आयोजित तहसील समाधान दिवस के दौरान भूमि विवाद से जुड़ा एक मामला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्र के निवासी अहसान खां ने जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को प्रार्थना पत्र सौंपकर अपनी कृषि भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास का आरोप लगाया है।

प्रार्थी के अनुसार, उनकी कृषि भूमि से संबंधित विवाद न्यायालय में विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा यथास्थिति बनाए रखने का उल्लेख भी किया गया है। इसके बावजूद विपक्षी पक्ष द्वारा खेत की मेड़ तोड़कर भूमि जोतने और कब्जा करने की बार-बार कोशिश की जा रही है।

अहसान खां ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि जब मामला अदालत में लंबित है, तब किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध है। उन्होंने अपनी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और संबंधित पक्ष के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई किए जाने की अपील की है।

तहसील समाधान दिवस में अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले को संज्ञान में लिया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, शिकायत की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रकरण जांच प्रक्रिया में है और निर्णय जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।